UTs including Gujarat are (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP), (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and Employment Assurance Scheme (EAS).

The Integrated Rural Development Programme (IRDP) is a Self Employment programme aimed at creating self employment opportunities for familes living below the poverty line in rural areas by providing financial assistance in the form of subsidy by the Govt, and term credit advanced by financial institutions for income generating activities.

Jawahar Rozgar Yogana (JRY) and Employment Assurance Scheme (EAS) are wage employment programme being implemented in Gujarat for providing sustainable employment to the rural poor.

The details of physcial and financial performance for the last three years under the schemes of IRDP, JRY and EAS are as under:—

	Year	Allocation (Rs.in lakhs)	Utilisation	Physical Target	Physical Achievement
				(Familie	s in Nos.)
Ke					
IRDP.	1993-94	3090.00	3354.85	74909	79725
	1994-95	3063.00	3259.82	61262	76498
	1995-96	3059.22	3077.68	*	55686 Mandays Generated (Lakhs Mandays)
JRY **	1993-94	12925	11716	211	233
	1994-95	13835	14166	240	259
	1995-96	14004	12824	213	219
EAS:	1993-94	* **	146	***	7
	1994-95	»»*	1810	***	35
	1995-96	*»*	5752	***	92

* During 1995-96 the physical target was not fixed
** Including Intensified JRY.
*** EAS is a demand driven scheme and therefore, has not formal yearly allocation and target.

गुजरात में "कापार्ट" द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

1859. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में विशेषकर सूरत, भरूच, वलसाड़ और पंचमहल जिलों के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद (कापार्ट) द्वारा इसके आरंभ से लेकर जून, 1995 तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इन जिलों की किन-किन एजेंसियों को "कापार्ट" के माध्यम से सहायता दी गई है और ये एजेंसियां किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) ऐसी प्रत्येक एजेंसी को अब तक कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है और कितनी राशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार "कापार्ट" के अन्तर्गत मजदूर संघों को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है ताकि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) इसके आरंभ होने से लेकर और 30.6.1995 तक, कापार्ट ने गुजरात के सूरत, भड़ोच, वलसाड और पंचमहल जिलों में स्वयंसेवी एजेंसियों के लिए 129 परियोजनाएं संस्वीकृत की है।

(ख) और (ग) सूरत, भड़ौच, वलसाड और पंचमहल जिलों में कापार्ट द्वारा सहायता प्राप्त स्वयंसेवी एजेंसियों के ब्यौरे और इन एजेंसियों को 30.6.1995 तक संस्वीकृत राशि और रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)।

(घ) कापार्ट, स्वयंसेवी एजेंसियों को ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है न कि मजदूर संगठनों हेतु।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कापार्ट द्वारा गुजरात के सूरत, भड़ौच, वलसाड, पंचमहल जिलों में सहायता प्राप्त स्वयंसेवी एजेंसियों का ब्यौरा तथा इन एजेंसियों का 30.6.1996 तक रिलीज तथा मंजूर हुई राशि का ब्यौरा

क्रमांक	स्वयंसेवी एजेंसी का ब्यौरा	स्वीकृत राशि (रुपये में)	रिलीज राशि (रुपये में)
1	2	3	4
	जिला सूरत		
1.	सौगध विकास योजना पो०ओ० हिलवाडी तालुक सौगध (फोर्ट) जिला सूरत गुजरात	10,16,500	6,10,166
2.	वेदची सेवा समिति, पो०ओ० वालौड जिला सूरत	6,06,715	2,05,851
3.	गुजरात नवोदय मण्डल नियर हार्दिक असपताल सत्यम सोसाइटी, व्यारा, सूरत	8,56,380	4,56,800
4.	नवल भाव प्रतिष्ठान, शिक्षक संघ हरिनगर, उदना, हरिनगर जिला सूरत	2,82,600	2,82,600
5.	ग्रामीण तथा शहरी गुजरात एसोसिएशन 15, नर्मदा हाउस, पो०ओ० वल्लबनगर, सूरत	6,19,680	6,19,680
6.	श्री छत्रपति शिवाजी एजूकेशन ट्रस्ट, उदना तालुक चेरोयारी, जिला सूरत	1,61,500	80,750
7.	मानव कल्याण ट्रस्ट, पो०ओ० पोहारी वाया वालोड, जिला सूरत	8,99,400	7,04,395
	जिला भड़ौच		
8.	आदिजाति सेवा सजाज, श्री कोटी जिला भडौच, गुजरात	54,300	54,300

1	2	3	4
9.	ग्रामीण विकास सोसाइटी, सुभाष मैदान मुशर, जिला भडौच (गुजरात)	22,500	—
10.	अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा तथा संस्कृति (इन्रेका), काम्प्लेक्स, राजपिपला रोड डीडिया पाडा० जिला भडौच	1,44,75,645	1,13,15,711
11.	सोसाइटी फार एजूकेशन वेलफेयर एण्ड एक्शन रूरल, झगाडिया, जिला भडौच	75,23,000	75,23,000
12.	भारत यात्रा केन्द्र ओल्ड मजदा रोड, गांव एवं पो०ओ० डाडियापाडा जिला भडौच	4,14,000	—
	जिला वलसाड		
13.	वनाचंल ग्रामीण विकास मण्डल, 12, क्षितिज अपार्टमेंट, प्रथम तल, टीथल रोड, जिला वलसाड (गुजरात)	37,27,471	20,49,764
14.	आदिवासी मजूर कारीगर तथा कामगार विकास मण्डल, पो०ओ० प्रिया, वाया उदेवाटा जिला वलसाड	3,71,355	1,01,516
15.	अस्तित्व महिला उत्कर्ष संस्था सूरत अपार्टमैंट, हलार रोड क्रास लेन, जिला वलसाड	27,500	27,500
16.	श्री नवचेतन युवक मण्डल, कागवी, तालुक धर्मपुर, जिला वलसाड	4,14,000	2,07,000
17.	श्री नवचेतन ट्रस्ट, पो०ओ० धर्मपुर जिला वलसाड	4,14,000	2,07,000
18.	माधुरी महिला मण्डल पणिरा, जी-2/25, अतुल कालोनी, पो०ओ० अतुल जिला वलसाड	27,500	27,500
19.	पर्यावरण कलवानी मण्डल, पो०ओ० बालचोन्डी, वाया नानकोधा, जिला वलसाड (गुजरात)	14,40,752	10,39,128
20.	श्री शक्ति वर्धक युवा मंडल ग्राम/पो० पलधोरा जिला वलसाड	76,860	57,645
21.	भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज़ फाउंडेशन, सेनापति बापत मार्ग, पुणे (वलसाड जिले में भी स्वीकृत परियोजनाएं)	89,94,000	80,00,000
	पंचमहल जिला		
22.	एन०एम० सदगुरू वाटर एंड डेवलेपमेंट फाउंडेशन, पोस्ट बाक्स नं० 71, आर०टी०ओ० के पास नाका, ग्राम/पो० बाहोड, जिला-पंचमहल	1,60,61,520	1,23,97,940
23.	पानेलव औद्योगिक उत्पादक सहकारी मंडल, द्वारा पानालव ग्राम विकास केन्द्र, गांव पानालव, पो० ताजपुर, जिला-पानालव	3,45,950	3,17,573
24.	सोशल एक्शन फार रूरल एंड ट्राइबल इन इनहैबिटेंटस आफ गोधर वैस्ट, ए लूना वाडा, तालुक संतरामपुर, जिला-पंचमहल	12,08,360	11,67,970
25.	यादभेत विभाग सर्वांगी विकास मंडल, ग्राम-यादभेत, पो० गांधा, तालुका देवगाध, बारिया, जिला-पंचमहल	26,500	26,500
26.	गुजरात आदिवासी विकास परिषद कोर्ट रोड, ग्राम/पो० दाहोड, ज़िला-पंचमहल	6,08,000	6,08,000
27.	भील सेवा मंडल ग्राम/पो० दाहोड, जिला पंचमहल	26,500	26,500

क्रमांक	स्वयंसेवी एजेंसी का ब्यौरा	स्वीकृत राशि (रुपये में)	रिलीज राशि (रुपये में)
28.	रूरल डेवेलपमेंट सोसाइटी ग्राम/पोस्ट पानालव, जिला-पंचमहल	2,07,000	1,03,000
29.	सारथी पंचमहल, ग्राम/पोस्ट गोधारा पश्चिम, वाया लूनावारा, जिला-पंचमहल	5,83,000	2,00,000
30.	श्री धोरेला केलवानी मंडल स्थान धारघाला, तालुक-लिमखोडा, जिला-पंचमहल	2,07,000	1,03,000
31.	श्री सरस्वती केलवानी ट्रस्ट जाफराबाद, गोधरा पंचमहल, जिला-पंचमहल	1,58,887	1,58,887
32.	लोक विज्ञान सेवा संघ, ग्राम/पोस्ट ब्यारा, जिला-पंचमहल	4,14,000	2,02,400

Shelter Upgradation under Nehru Rozgar Yojana in Madhya Pradesh

1860. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any central scheme for shelter upgradation under Nehru Rozgar Yojana is being implemented by Government in Madhya Pradesh;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) the number of dwelling units upgraded under the scheme during the last three years, year-wise and district-wise;

(d) whether any target for 1996-97 has been fixed and funds earmarked for the State; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) to (c) Though the Scheme of Housing and Shelter Upgrada-tion (SHASU), one of the Schemes of the Nehru Rozgar Yojana, is being implemented in the country since October, 1989, the Government of Madhya Pradesh has not yet taken up the scheme for implementation.

(d) and (e) The subsidy funds to the tune of Rs. 68.80 lakhs under SHASU have been earmarked for Madhya Pradesh for 1996-97 with a target of 11,467 dwelling units to be upgraded.

मध्य प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना का कार्यान्वयन

1861. **श्री अजीत जोगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेस्वरलू): (क) योजना के प्रारम्भ में 1989-90 से 1995-96 तक मध्य प्रदेश सरकार को 5332.70 लाख रुपये की केन्द्रीय धनराशि दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए राज्य हेतु 480.00 लाख रुपये का केन्द्रीय नियतन किया गया है।

(ख) केन्द्रीय निधियां जिलों को सीधे ही जारी नहीं की जाती। केन्द्रीय निधियां राज्यों को जारी की जाती हैं फिर राज्य, निधियों को विभिन्न जिलों को देते हैं।

Import of LNG

1862. PROF. NAUNIHAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Petroleum has a proposal to import Liquefied Natural Gas;

(b) if so, the quantum of LNG prop osed to be imported and the reasons for doing so;